



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 6 जुलाई, 2005/15 आषाढ़, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कारण बताओ नोटिस

शिमला-171 009, 25 जून, 2005

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 89/2004-11130.—यह कि जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर ने उनके कार्यालय पत्र संख्या पी० सी० एच०-एच० एम० आर० (मझोग सुल्तानी)-8389, दिनांक 5-2-2005 के अनुसार सूचित किया है कि आपको हिमाचल प्रदेश सरकार की भूमि खसरा नम्बर 95/1 व 95/2, रकबा 4 कनाल 11 मरले पर अवैध कब्जा के लिए न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), हमीरपुर द्वारा दिनांक 21-11-2000 को दिये गये फैसले के अनुसार दोषी पाया गया था। उक्त फैसले के विरुद्ध आप द्वारा दायर अपील पर न्यायालय समाहर्ता उप-मण्डल [उप-मण्डलाधिकारी (ना०)], हमीरपुर द्वारा दिनांक 3-2-2005 को दिये गये निर्णय में आप द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जे की पुष्टि की है। दिसम्बर, 2000 में प्रधान, ग्राम पंचायत मझोग सुल्तानी के पद पर चुनाव हेतु नामांकन पत्र में आपने घोषणा की है कि आप द्वारा किसी भी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अतः उपरोक्त अतिक्रमण तथा मिथ्या घोषणा करके आपने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(ग) व (द) के अन्तर्गत अयोग्यता अर्जित करने उपरान्त उपायुक्त, हमीरपुर द्वारा उनके कार्यालय आदेश संख्या पी० सी० एच०-एच०

एम० आर० (मशोग सु०)-8343-58, दिनांक 4-2-2005 के अन्तर्गत आपको ग्राम पंचायत मशोग सुल्तानी के प्रधान पद से अयोग्य घोषित किया गया है ;

यह कि आप द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण तथा मिथ्या घोषणा कर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(ग) व (ङ) के अन्तर्गत अयोग्यता अर्जित करने के फलस्वरूप आपको हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1)(क) के अन्तर्गत प्रधान, ग्राम पंचायत मशोग सुल्तानी के पद से निष्कासित किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से आपको निर्देश दिये जाते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्यों के लिये आपको प्रधान, ग्राम पंचायत मशोग सुल्तानी के पद से निष्कासित किया जाये । आप उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर दें । आपका उत्तर निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते तथा मामले में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

शिमला-171 009, 25 जून, 2005

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 27/99-11144.—यह कि उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने उनके कार्यालय पत्र संख्या पंच-के० जी० आर०-ई० (14) 44/91-10879, दिनांक 1-2-2005 के अनुसार सूचित किया है कि आप द्वारा सरकारी भूमि खसरा नम्बर 917/1, रकबा 0-01-70 पर कब्जा होने वाले श्री भदन लाल पुत्र नौधू राम, निवासी लुधियाड, जिला कांगड़ा से शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था । उक्त शिकायत की पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, नगराटा सुरियां तथा तहसीलदार ज्वाली से करवाई गई । खण्ड विकास अधिकारी, नगराटा सुरियां व तहसीलदार, ज्वाली ने अपनी रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त सरकारी भूमि पर आप द्वारा कब्जे की पुष्टि की है । इसके अतिरिक्त उक्त सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के नियमितकरण हेतु भी आप द्वारा गपथ-पत्र दायर किया गया है । दिसम्बर, 2000 में उप-प्रधान, ग्राम पंचायत लुधियाड के पद पर चुनाव हेतु नामांकन पत्र में आपने घोषणा की है कि आप द्वारा किसी भी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है । अतः उपरोक्त अतिक्रमण तथा मिथ्या घोषणा करके आपने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(ग) व (ङ) के अन्तर्गत अयोग्यता अर्जित करने उपरान्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा उनके कार्यालय आदेश संख्या पंच के० जी० आर०-ई० (14) 44/91-4447-51, दिनांक 2-9-2004 व पंच के० जी० आर०-ई० (14) 44/9194-10390, दिनांक 20-12-2004 के अन्तर्गत आपको ग्राम पंचायत लुधियाड के उप-प्रधान पद से अयोग्य घोषित किया गया है ;

यह कि आप द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण तथा मिथ्या घोषणा कर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) व (ङ) के अन्तर्गत अयोग्यता अर्जित करने के फलस्वरूप आपको हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) (क) के अन्तर्गत उप-प्रधान, ग्राम पंचायत लुधियाड के पद से निष्कासित किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से आपको निर्देश दिये जाते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्यों के लिये आपको उप-प्रधान, ग्राम पंचायत लुधियाड के पद से निष्कासित किया जाये । आप उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर दें । आपका उत्तर निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि आप अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते तथा मामले में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

शिमला-171009, 25 जून, 2005

संख्या: पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 50/2003-11137.—यह कि उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने उनके कार्यालय पत्र संख्या पंच-के० जी० आर०-ई० (50) 91-10878, दिनांक 1-2-2005 के अनुसार सूचित किया है कि आप द्वारा सरकारी भूमि खेवट नम्बर-142 मिन, खतौनी नम्बर-160 मिन, खसरा नम्बर 295, रकबा 0-33-38, मुहल बन बंजर, पटवार वृत्त पपलाह पर कब्जा होने वाले प्रधान, ग्राम पंचायत पपलाह, जिला कांगड़ा से शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था। उक्त शिकायत की पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, लम्बागांव तथा उप-मण्डलाधिकारी (ना०) जयसिंहपुर से करवाई गई। खण्ड विकास अधिकारी लम्बागांव ने अपनी रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त सरकारी भूमि पर आप द्वारा कब्जे की पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त उक्त सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के निमित्तकारण हेतु भी आप द्वारा उपमण्डलाधिकारी (ना०) जयसिंहपुर के कार्यालय में शपथ-पत्र दायर किया गया है। दिसम्बर, 2000 में पंचायत सदस्य, वार्ड नम्बर-2, ग्राम पंचायत पपलाह के पद पर चुनाव हेतु नामांकन-पत्र में आपने घोषणा की है कि आप द्वारा किसी भी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अतः उपरोक्त अतिक्रमण तथा मिथ्या घोषणा करके आपने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ग) व (ङ) के अन्तर्गत अयोग्यता अर्जित करने उपरान्त उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा उनके कार्यालय आदेश संख्या पंच-के० जी० आर०-ई० (50)/91-4336-40, दिनांक 30-8-2004 व पंच-के० जी० आर०-ई० (50) 91-10309-12 दिनांक 20-12-2004 के अन्तर्गत आपको वार्ड नं० 2, ग्राम पंचायत, पपलाह के सदस्य पद से अयोग्य घोषित किया गया है;

यह कि आप द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण तथा मिथ्या घोषणा कर हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ग) व (ङ) के अन्तर्गत अयोग्यता अर्जित करने के फलस्वरूप आपको हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) (क) के अन्तर्गत सदस्य, ग्राम पंचायत पपलाह के पद से निष्कासित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः इस कारण बनाओ नोटिस के माध्यम से आपको निर्देश दिए जाने हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्यों के लिये आपको सदस्य, ग्राम पंचायत, पपलाह के पद से निष्कासित किया जाए। आप उक्त कारण बनाओ नोटिस का उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर दें। आपका उत्तर निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते तथा मामले में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

शिमला-171009, 25 जून, 2005

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 93/2004-11158.—यह कि उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने उनके कार्यालय पत्र संख्या पंच-के० जी० आर०-ई० (15) 18/91-10875 दिनांक 1-2-2005 के अनुसार सूचित किया है कि आप द्वारा सरकारी भूमि खसरा नम्बर 444/1, रकबा तादादी 0-15-32 पर कब्जा होने वाले प्राप्त शिकायत पत्र की पुष्टि तहसीलदार, जयसिंहपुर से करवाई गई। तहसीलदार, जयसिंहपुर ने अपनी रिपोर्ट में उपरोक्त सरकारी भूमि पर आप द्वारा कब्जे की पुष्टि की है। दिसम्बर, 2000 में उप-प्रधान, ग्राम पंचायत, कोटलू के पद पर चुनाव हेतु नामांकन पत्र में आपने घोषणा की है कि आप द्वारा किसी भी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अतः उपरोक्त अतिक्रमण तथा मिथ्या घोषणा करके आपने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ग) व (ङ) के अन्तर्गत अयोग्यता अर्जित करने उपरान्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा उनके कार्यालय आदेश संख्या पी० सी० एच०-के० जी० आर०-ई० (15) 18/91-9670-75, दिनांक 17-11-2004 व पी० सी० एच०-के० जी० आर०-ई० (15) 18/91-9934-39 दिनांक 6-12-2004 के अन्तर्गत आपको ग्राम पंचायत, कोटलू के उप-प्रधान पद से अयोग्य घोषित किया गया है;

यह कि आप द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण तथा मिथ्या धोषणा कर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ग) व (ड) के अन्तर्गत अयोग्यता अर्जित करने के फलस्वरूप आपको हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146(1) (क) के अन्तर्गत उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कोटनू के पद से निष्कासित किया जाना प्रस्तावित है।

इतः इस कारण वताओ नोटिस के माध्यम से आपको निर्देश दिए जाते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्यों के लिये आपको उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कोटनू के पद से निष्कासित किया जाए। आप उक्त कारण वताओ नोटिस का उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर दें। आपका उत्तर निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते तथा मामले में हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तहसीलदार, जयसिंहपुर द्वार प्रेषित रिपोर्ट की प्रति साथ संलग्न है।

शिमला-171009, 25 जून, 2005

संख्या पी0सी0एच-0एच0ए0(5)44/2001-11172.—यह कि उपायुक्त, चम्बा द्वारा श्री माधो राम, प्रधान, ग्राम पंचायत शिन्लाघाट, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के पद से सरकारी धनराशि के दुरुपयोग, विस्तीर्ण अनियमितताओं, अपने कर्तव्य निर्वहन में आपत्तिजनक कार्य क्लाप के फलस्वरूप उनके कार्यालय आदेश सं0-505-12 दिनांक 30-6-2004 द्वारा निलम्बित किया गया था;

यह कि उपायुक्त, चम्बा द्वारा मामले की वास्तविकता जानने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा, जिला चम्बा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया;

यह कि जांच अधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट उपायुक्त चम्बा के माध्यम से दिनांक 4-2-2005 को निदेशालय में प्राप्त हुई तथा प्राप्त जांच रिपोर्ट में दर्शाये गये तथ्यों का वारीकी से अध्ययन करने उपरान्त जो आरोप श्री माधो राम, प्रधान के विरुद्ध भिन्न पाये गये उनका विवरण निम्न है:—

1. प्रधान द्वारा सरकारी भूमि पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना तथा पंचायत के नाम भूमि हस्तांतरण किये वगैर सराये, गैस्ट हाऊस तथा दो दुकानों का निर्माण किया गया है जबकि उक्त निर्माण कार्य पंचायत के नाम भूमि हस्तांतरण उपरान्त किया जाना चाहिए था।
2. गैस्ट हाऊस, चार दुकानों व दो स्टोर्न के निर्माण पर निर्माण सामग्री का व्यय अधिक किया गया है। सहायक अभियन्ता (विकास), ग्रामीण विकास अधिकरण, चम्बा द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार चार दुकानों व दो स्टोर्न के निर्माण में निर्माण सामग्री मु0 33,812/- रु0 तथा गैस्ट हाऊस के निर्माण में मु0 11,308/- रु0 की राशि के निर्माण सामग्री का व्यय किया गया है। इस प्रकार प्रधान से मु0 45,120/- रु0 की व्यय की जाती है।
3. गांव नरैनी में बावडी का निर्माण स्वीकृत स्थान पर न करके प्रधान द्वारा अपनी मर्जी से अन्य स्थान पर किया गया है।
4. प्राथमिक पाठशाला ग्रोवल के निर्माण हेतु का कार्य ठेके पर देकर मु0 55,760/- रु0 व्यय किया गया तथा स्कूल का निर्माण गांव केंद्र के वज्राये गांव केहल और ग्रोवल के मध्य में शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना किया गया है। 11/2001 को स्कूल का कार्य शुरू किया गया तथा फरवरी, 2002 को नांव तक निर्माण कार्य करके कार्य बन्द कर दिया गया है। जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान

इस बारे में प्रधान से पूछने पर प्रधान ने बताया कि उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा चम्बा के आदेशानुसार कार्य बन्द कर दिया गया था। परन्तु शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश की प्रति प्रधान प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। बिल अनुसार 60 वेग सीमेंट इस निर्माण कार्य हेतु क्रय किया गया दर्शाया गया है परन्तु बिल में क्रय दिनांक नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रधान द्वारा स्कूल का निर्माण निर्धारित अवधि के भीतर न करके राशि का दुरुपयोग किया है।

5. प्रधान द्वारा निम्न अवधि में निम्न राशि अनाधिकृत रूप से अपने पास रख कर राशि का दुरुपयोग किया है :—

राशि	अवधि	कुल दिन
मु० 9071/- रु०	5 मार्च 8 दिन	158 दिन
मु० 3783/- रु०	18-9-2003 से 12-1-2004	117 दिन
मु० 12,731.40 रु०	31-10-2001 से 26-12-2001	57 दिन
मु० 22,280/- रु०	1-3-2001 से 10-4-2001 तक	41 दिन
मु० 19,883/- रु०	27-4-2001 से 2-6-2001 तक	37 दिन
मु० 34,418/- रु०	16-6-2001 से 19-7-2001 तक	34 दिन

उपरोक्त अवधि में प्रधान द्वारा अनाधिकृत रूप से अपने पास रखी गई राशि पर 12.5 प्रतिशत की दर से मु० 1854-54 की वसूली प्रधान से की जानी है।

अतः आप द्वारा बरती गई उक्त विभिन्न विस्तृत अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्य निर्वहन में आपत्ती-जनक कार्यकलाप के फलस्वरूप आप हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) (ख) के अन्तर्गत अवचार के दोषी है।

अतः इस कारण बनाओ नोटिस के माध्यम से आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 की उप धारा (1) के अन्तर्गत अवसर दिया जाता है कि उपरोक्त कृत्यों के लिए क्यों न आपको प्रधान के पद से निष्कासित किया जाए।

आपका उत्तर इस कारण बनाओ नोटिस प्राप्त के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जाएगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं और इस मूल में आपके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उप-मण्डलाधिकारी (ना०) चम्बा, जिला चम्बा द्वारा की गई जांच रिपोर्ट संलग्न है।

जिमला-171009, 25 जून, 2005

संख्या पीसीएच-एचए (5) 66/2003-11179. —यह कि उपायुक्त, कांगड़ा स्थित भ्रमशाला, जिला कांगड़ा ने उनके कार्यालय पत्र संख्या पंच-केजीआर-ई०(9) 14/91-10877, दिनांक 1-2-2005 के अनुसार सूचित किया है कि आप द्वारा सरकारी भूमि खसरा नम्बर 40, 41 और 42/2, रकबा 0-00-24, 0-02-62 व 0-06-96 पर कब्जा होने वाले श्री रघु नाथ निवामी जबड़, जिला कांगड़ा में शिकायत-पत्र प्राप्त हुआ था। उक्त शिकायत पत्र की पुष्टि तहसीलदार, फतेहपुर से करवाई गई। तहसीलदार, फतेहपुर ने

अपनी रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त सरकारी भूमि पर आप द्वारा कब्जे की पुष्टि की है। दिसम्बर, 2000 में प्रधान, ग्राम पंचायत मच्छोट के पद पर चुनाव हेतु नामांकन पत्र में आपने घोषणा की है कि आप द्वारा किसी भी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अतः उपरोक्त अतिक्रमण तथा मिथ्या घोषणा करके आपने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(ग) व (ड) के अन्तर्गत अयोग्यता अर्जित करने उपरान्त उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा उनके कार्यालय आदेश संख्या पंच-के0 जी0 आर0-ई0(9) 14/91-2892-98 दिनांक 8-6-2004 व पंच-के0 जी0 आर0 ई0(9) 14/91-10300-304 दिनांक 20-12-2004 के अन्तर्गत आपको ग्राम पंचायत मच्छोट के प्रधान पद से अयोग्य घोषित किया गया है;

यह कि आप द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण तथा मिथ्या घोषणा कर हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(ग) व (ड) के अन्तर्गत अयोग्यता अर्जित करने के फलस्वरूप आपको हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1)(क) के अन्तर्गत प्रधान, ग्राम पंचायत, मच्छोट के पद से निष्कासित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से आपको निर्देश दिए जाते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्यों के लिए आपको प्रधान, ग्राम पंचायत, मच्छोट के पद से निष्कासित किया जाए। आप उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर दें। आपका उत्तर निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते तथा मामले में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तहमीलदार फतेहपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की प्रति साथ संलग्न है।

जिमला-171009, 25 जून, 2005

संख्या पी0 जी0 एच0-एच0 ए0 (5) 11165. —यह कि उपायुक्त, हमीरपुर द्वारा श्री रूप चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत बलू, विकास खण्ड नदौन, जिला हमीरपुर के पद से सरकारी धनराशि के दुरुपयोग, विनीय अनियमितताओं, अपने कर्तव्य निर्वहन में आपत्तिजनक कार्यकलाप के फलस्वरूप उनके कार्यालय आदेश संख्या 690-97, दिनांक 20-2-2004 द्वारा निलम्बित किया गया था;

यह कि उपायुक्त हमीरपुर द्वारा मामले की वास्तविकता जानने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत उप-मण्डलाधिकारी (ना0) नदौन, जिला हमीरपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया;

यह कि जांच अधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट उपायुक्त, हमीरपुर के माध्यम से दिनांक 5-3-2005 को निदेशालय में प्राप्त हुई तथा प्राप्त जांच रिपोर्ट में दर्शाये गये तथ्यों का बारीकी से अध्ययन करने उपरान्त जो आरोप श्री रूप चन्द, प्रधान के विरुद्ध सिद्ध पाये गये उनका विवरण निम्न है: —

1. दिनांक 11-9-2002 तथा दिनांक 26-9-2002 को कार्यवाही रजिस्टर अनुसार उपस्थिति 3/7 होने के कारण कोरम अपूर्ण रहने पर भी उन द्वारा बैंक खातों से राशि की निकासी की गई है। पंचायत को कार्रवाई रजिस्टर के पृष्ठ 170 प्रस्ताव संख्या 4 व 5 बाद में तथा कार्यवाही दायिग्य में बाहर लिखे गये हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि इस मामले में श्री रूप चन्द, प्रधान दोषी है।
2. वर्ष 2002-03 में 11वें वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत प्राप्त राशि को स्वीकृत स्कीमों के अनुसार व्यय न करके इसे ग्रामीण भवनर्जी में सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर अन्य स्कीमों पर व्यय किया गया है।

3. वर्ष 2002-03 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि को स्कीमों अनुसार व्यय न करके अवैध रूप से व अपनी मनमर्जी से हैण्ड पम्प कुंआ माई पर व्यय किया गया।
4. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का मु० 11,400 रु०, दिनांक 28-10-2002 को निकाल कर एवं पंचायत से अग्रिम बाबत निर्माण प्राप्त करके डम राशि का दिनांक 29-10-2002 में 6-2-2003 तक निजी प्रयोग करके इस सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है। श्री रूप चन्द, प्रधान के ब्यान अनुसार कार्य आरम्भ होते ही वन्तदारों ने झगड़ा डाल दिया जिससे कार्य पूर्ण करने में विलम्ब हो गया। यदि वन्तदारों ने झगड़ा डाला था तो श्री रूप चन्द, प्रधान को चाहिये था कि निकाली गई राशि बैंक में जमा करवाने। इस प्रकार श्री रूप चन्द, प्रधान ने धनराशि अपने पास रख कर राशि का दुरुपयोग किया। प्रधान ने मु० 1517 रु० ब्याज के रूप में जमा करवाए हैं। जिससे प्रधान पर यह आरोप भी सिद्ध पाया गया।

अतः आप द्वारा बरती गई उपरोक्त विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्य निर्वहन में आपत्तिजनक कार्यकलाप के फलस्वरूप आप हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) (ख) के अन्तर्गत अवचार के दोषी हैं।

अतः इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये अवसर दिया जाता है कि उपरोक्त कृत्यों के लिये क्यों न आपको प्रधान पद से निष्कासित किया जाय।

आपका उत्तर इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को पहुंच जाना चाहिये। निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं और इस सूरत में आपको विरुद्ध हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उपमण्डलाधिकारी (ना०), कांगड़ा द्वारा की गई जांच रिपोर्ट संलग्न है।

आदेश

शिमला-171009, 28 जून, 2005

संख्या पी सी एच-एच ए (5) 11368-74.—जबकि अध्यक्ष, लोकमित्र परियोजना, हमीरपुर के माध्यम से समस्त निवासी ग्राम पंचायत, जाहू का श्री राम रखा, प्रधान, ग्राम पंचायत जाहू के विरुद्ध गुजरात भूकम्प राहत की राशि को गायब करने बारे प्राप्त शिकायत पत्र पर प्रारम्भिक छानबीन उपरान्त श्री राम रखा, प्रधान ग्राम पंचायत जाहू को उपायुक्त हमीरपुर द्वारा दिनांक 17-5-2004 को प्रधान, ग्राम पंचायत जाहू के पद से निलम्बित किया गया था ;

जबकि मामले की वास्तविकता जानने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अन्तर्गत उपायुक्त, हमीरपुर द्वारा उनके कार्यालय के पत्र संख्या पी सी एन-एच एम आर (5) (इ) 1/2004-2307, दिनांक 21-5-2004 द्वारा नियमित जांच उप-मण्डलाधिकारी (ना०) हमीरपुर, जिला हमीरपुर को सौंपी गई;

और जबकि जांच अधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट उपायुक्त, हमीरपुर से उनके कार्यालय पत्र-संख्या 215, दिनांक 19-4-2005 के अन्तर्गत निदेशालय में प्राप्त हुई तथा जांच रिपोर्ट में दर्शाये गये तथ्यों का बारीकी से अध्ययन करने उपरान्त सरकार के ध्यान में आया कि ग्राम पंचायत जाहू द्वारा दिनांक 4-2-2001 को प्रस्ताव पारित कर गुजरात में भूकम्प से पीड़ित लोगों के लिए राशि एकत्रित करने हेतु रसीद बुकें छपवाने

का निर्णय लिया गया। जिसके दृष्टिगत इस उद्देश्य हेतु 10 रसीद बुकों छपवाई गई। इन रसीद बुकों को सभी पंचों को राशि एकत्रित करने हेतु बांट दिया गया। जिनमें से 8 रसीद बुकों से एकत्रित राशि, जो मु० 3910/- रुपये बनती थी उसे इन सदस्यों द्वारा श्री राम रखा, प्रधान, ग्राम पंचायत, जाहू के पास जमा करवा दी थी और दो पंचों सर्वश्री सर्वजीत तथा धनी राम, पंच द्वारा एकत्रित धनराशि को जमा नहीं करवाया गया। परन्तु पंचायत द्वारा इन रसीद बुकों का कोई भी रिकार्ड नहीं रखा गया और न ही पंचायत प्रधान द्वारा इस राशि को पंचायत लेखा में जमा करवाया गया। इस तरह प्रधान द्वारा उपरोक्त राशि मु० 3910/- रु० को अपने निजी प्रयोग में लाकर इसका दुरुपयोग किया। परन्तु प्रधान ने जांच के दौरान व्यान किया कि ग्राम पंचायत की हर बैठक में उपरोक्त एकत्रित राशि को जमा करने बारे चर्चा होती रही तथा यही फैसला लिया जाता रहा कि अन्य दो पंचों से भी एकत्रित राशि की प्राप्ति उपरान्त एक मुश्त में समस्त राशि को जमा करवा दिया जायेगा। अतः अब प्रधान, ग्राम पंचायत जाहू ने मु० 3910/- रु० दिनांक 23-1-2004 को माननीय मुख्य मन्त्री राहत कोष में जमा करवा दिया है तथा मु० 1374 रु० व्याज पंचायत निधि में जमा करवा दिये हैं। इसके अतिरिक्त उपरोक्त दोनों पंचों द्वारा भी मु० 1532/- रु० राशि दिनांक 27-7-2004 को पंचायत निधि में जमा कर दी है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(6) के अन्तर्गत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुए, श्री राम रखा, प्रधान ग्राम पंचायत, जाहू, को भविष्य में अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव।